भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4040 का उत्तर

पश्चिम बंगाल में स्वीकृत की गई रेलवे परियोजनाएं

4040. श्रीमती माला राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन महीनों के दौरान सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए स्वीकृत की गई रेलवे परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) विगत तीन महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में चल रही परियोजनाओं/नई परियोजनाओं हेतु कितनी निधि जारी की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परियोजनाओं के लिए बजट आबंटन किसी परियोजना में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	4,380 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2026-27	14,205 करोड़ रु. (3 गुना से अधिक)

स्वीकृत परियोजनाएं:

01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 83,433 करोड़ रुपए की लागत से कुल 5,148 कि.मी. लंबाई की 63 परियोजनाएं (14 नई लाइन, 04 आमान परिवर्तन और 45 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	14	1,056	337	13,872
आमान परिवर्तन	4	1,201	854	3,676
दोहरीकरण/बहुपथन	45	2,891	530	10,401
कुल	63	5,148	1,721	27,949

हाल ही में पूरी की गईं परियोजनाएं:

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	रामपुरहाट-मंदारहिल नई लाइन (130 कि.मी.)	908
2	आजिमगंज-मुर्शिदाबाद नई लाइन (7 कि.मी.)	164
3	बर्द्धमान-कटवा आमान परिवर्तन (52 कि.मी.)	696
4	अहमदपुर-कटवा आमान परिवर्तन (52 कि.मी.)	440
5	पाँशकुड़ा-खड़गपुर दोहरीकरण (45 कि.मी.)	408
6	लालगोला-जियागंज दोहरीकरण (23 कि.मी.)	124
7	कृष्णनगर-बेथुयाडहरी दोहरीकरण (28 कि.मी.)	152
8	नबद्वीपधाम-पाटुली दोहरीकरण (22 कि.मी.)	170
9	बेथुयाडहरी-पलासी दोहरीकरण (23 कि.मी.)	132
10	अम्बिका कालना-नबद्वीपधाम दोहरीकरण (23 कि.मी.)	145

11	नलहाटी-सागरदिघि दोहरीकरण (26 कि.मी.)	193
12	तमलुक जंक्शन- बासुलिया सुताहाटा दोहरीकरण (24 कि.मी.)	245
13	पलासी-जियागंज दोहरीकरण (54 कि.मी.)	234
14	आजिमगंज-मणिग्राम दोहरीकरण (21 कि.मी.)	150
15	न्यू कूचबिहार-गुमानीहाट दोहरीकरण (29 कि.मी.)	330
16	न्यू कूचबिहार-सामुकतला रोड दोहरीकरण (29 कि.मी.)	445
17	सांइथिया-तारापीठ तीसरी लाइन (22 कि.मी.)	186
18	आमबाड़ी फालाकाटा - न्यू मैनागुड़ी दोहरीकरण (38 कि.मी.)	843
19	बैण्डेल-बैंची-तीसरी लाइन (31 कि.मी.)	546
20	बैंची-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन (26 कि.मी.)	424
21	बाज़ार सौ-आजिमगंज जंक्शन दोहरीकरण (42 कि.मी.)	343
22	सागरदिघी-मालदा टाउन दोहरीकरण (25 कि.मी.)	248
23	खड़गपुर-नारायणगढ़ तीसरी लाइन (24 कि.मी.)	270
24	मनिग्राम-निमतिता दोहरीकरण (24 कि.मी.)	713
25	पुरुलिया-कोटशिला दोहरीकरण (36 कि.मी.)	393

चालू परियोजनाएं:

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1	चाण्डिल-दामोदर तीसरी लाइन (121 कि.मी.)	1,932

2	तारकेश्वर-बिष्णुपुर नई लाइन (83 कि.मी.)	1,542
3	सिवोक-रंगपो नई लाइन (44 कि.मी.)	11,973
4	बालुरघाट-हिली नई लाइन (30 कि.मी.)	1,209
5	कालियागंज - बुनियादपुर नई लाइन (33 कि.मी.)	1,147
6	कटिहार-कुमेदपुर और कटिहार - मुकुरिया दोहरीकरण (65 कि.मी.)	943
7	खड़गपुर-आदित्यपुर तीसरी लाइन (132 कि.मी.)	3,450
8	नारायणगढ़-भद्रक तीसरी लाइन (153 कि.मी.)	3,425
9	कालीपहाड़ी-बख्तरनगर 5वीं लाइन (18 कि.मी.)	350
10	डानकुनि-बाल्टीकुरी तीसरी और चौथी लाइन (18 कि.मी.)	429
11	मुरारई-बड़हरवा तीसरी लाइन (49 कि.मी.)	935
12	राणाघाट-कृष्णानगर सिटी तीसरी लाइन (26 कि.मी.)	446
13	अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन (57 कि.मी.)	1,630
14	साइंथिया - पाकुड़ चौथी लाइन (81 कि.मी.)	1,569
15	सांतरागाछी - खड़गपुर चौथी लाइन (111 कि.मी.)	2,905
16	बारबेंडा-दामरुघुतु दोहरीकरण, दामरुघुतु-बोकारो स्टील सिटी तीसरी और चौथी लाइन (52 कि.मी.)	815
17	राणाघाट-बनगांव दोहरीकरण (33 कि.मी.)	396
18	यार्ड तीसरी लाइन (6 कि.मी.) के रास्ते हिजली से निमपुरा	234
19	न्यू जलपाईगुड़ी- सिलीगुड़ी (7 कि.मी.) का दोहरीकरण	215
20	ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी दोहरीकरण (56 कि.मी.)	916
21	रामपुर हाट (12 कि.मी.) पर बाईपास लाइन	190

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली निम्नलिखित परियोजनाएं जिन्हें पिछले तीन महीनों में स्वीकृत किया गया है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	रामपुरहाट बाईपास (12 कि.मी.)	190
2	ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी दोहरीकरण (56 कि.मी.)	916
3	निमपुरा-मिदनापुर तीसरी लाइन (15 कि.मी.)	439

रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

राज्य सरकार के साथ समन्वयः

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में रेल संपर्क परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समन्वयन को सुदृढ़ बनाने, ऐसी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने एवं कार्यान्वयन के मुद्दों के समन्वित समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

चिंगड़ीघाटा मामलाः

इसके अलावा, अनुरोध किए जाने के लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात मई 2026 में कोलकाता मेट्रो के निर्माण के लिए वायाडक्ट खंडों के कार्य को आरंभ करने हेतु चिंगड़ीघाटा क्रॉसिंग पर यातायात के अस्थायी मार्ग परिवर्तन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। चिंगड़ीघाटा क्रॉसिंग के कार्यों को अंततः मई, 2026 में पूरा कर लिया गया है।

रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां

- **क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति**
- **विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या**

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

ऊपरी/निचले सड़क पुलः

भारतीय रेल पर समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा और रेलगाड़ियों की गतिशीलता पर उनके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके उन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-26 (मई, 2026 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-26 (मई, 2026 तक)	14,451 अदद (पश्चिम बंगाल राज्य में 547 अदद)

01.06.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में लगभग ₹1,17,492 करोड़ की लागत से 4,993 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों को मंज़ूरी दी गई है, इनमें पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग ₹8,060 करोड़ की लागत से 363 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्य शामिल हैं, जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2026-27 (मई, 2026 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल 09 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्य पूरे किए गए हैं।

पिछले तीन महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 1,460 करोड़ रुपए की लागत से 15 ऊपरी सड़क पुल और 24 निचले सड़क पुल कार्यों को मंजूरी दी गई है।

किसी ऊपरी/निचले सड़क पुल का कार्य पूरा होना और कमीशन करना, समपार बंद करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग का संरेखण निर्धारित करने, सामान्य व्यवस्था आरेख के अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण विशिष्ट परियोजना/कार्य स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के दिनों की अवधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करना व्यवहार्य नहीं है।

01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अंतिम रूप न दिए जाने, कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों आदि के कारण 99 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्य रुके हुए थे। बहरहाल, पिछले ढाई महीने में, ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए कई पहल की गई हैं:

(i) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, स्थानीय निकायों और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यदल गठित किया है जो ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित निर्णय को सक्रियता से मंजूरी दे रहा है।

(ii) परिणामस्वरूप, सभी रुके हुए/विलंबित कार्यों के लिए स्थल का संयुक्त दौरा किया जा रहा है और भूमि अधिग्रहण से पहले आवश्यक व्यवहार्य संरेखण को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। संरेखण को अंतिम रूप देने को सुविधाजनक बनाने के लिए, पश्चिम बंगाल/लोक निर्माण विभाग सरकार ने एक चेक लिस्ट भी जारी की है।

(iii) इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों के लिए सरकारी भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

उपर्युक्त उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण, अब तक, सभी 99 स्थानों पर स्थल के संयुक्त दौरे आयोजित किए गए हैं और 26 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों का पहले ही समाधान किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे ने ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।
ii. ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के पदधारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।
iii. डिजाइन अनुमोदन के दौरान देरी से बचने के लिए रेलवे हिस्से पर सड़क के फैलाव, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे शीघ्र नियोजन हेतु रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

स्टेशन पुनर्विकास:

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और चरणबद्ध रूप में उनका कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर योजना बनाने में प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं:

- रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- शहर के दोनों भागों के साथ रेलवे स्टेशन का एकीकरण

- रेलवे स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर का प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र का विकास
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- एयर कॉनकोर्स, एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, मल्टीमॉडल एकीकरण, भूसुदर्शनीकरण आदि की व्यवस्था।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान आदि तथा रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की संकल्पना भी की गई है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु 1,340 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 102 स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पश्चिम बंगाल	102	आद्रा, अलीपुरद्वार जं., अलुआबाड़ी रोड, अंबिका कालना, अनारा, अंडाल जं., अंदुल, आसनसोल जं., अजीमगंज, बगनान, बल्ली, बालुरघाट, बैण्डेल जं., बनगांव जं., बांकुरा, बाराभूम, बारासात, बर्धमान, बैरकपुर, बेल्दा, बरहामपुर कोर्ट, बेथुयाडाहरी, भालुका रोड, बिन्नागुड़ी, बिष्णुपुर, बोलपुर

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
		शांतिनिकेतन, बर्नपुर, कैनिंग, चंदन नगर, चांदपारा, चंद्रकोना रोड, दलगांव, दलखोला, डानकुनी, धुलियान गंगा, धुपगुड़ी, दीघा, दिनहाटा, दमदम जं., फालाकाटा, गरबेटा, गेडे, हल्दिया, हल्दीबाड़ी, हरिश्चंद्रपुर, हासीमारा, हिजली, हावड़ा जं., जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, जंगीपुर रोड, झालिदा, झारग्राम, जॉयचंडी पहाड़ जं., कालियागंज, कल्याणी, कल्याणी घोषपाड़ा, कामाख्यागुड़ी, कटवा जंक्शन, खगराघाट रोड, खड़गपुर जंक्शन, कोलकाता, कृष्णनगर सिटी जंक्शन, कुमेदपुर जंक्शन, मधुकुंडा, मध्यमग्राम, मालदा कोर्ट, मालदा टाउन, मेचेदा, मेदिनीपुर (मिदनापुर), नवद्वीप धाम, नैहाटी जंक्शन, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू फरक्का जंक्शन, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, न्यू माल जंक्शन, ओंडाग्राम, पानागढ़, पांडबेश्वर, पंसकुरा जंक्शन, पुरुलिया जंक्शन, रामपुरहाट जंक्शन, राणाघाट, सैंथिया जंक्शन, सालबोनी, समसी, सांतरागाछी, सियालदह, शालीमार, शांतिपुर, शेवड़ाफुली जंक्शन, श्रीरामपुर, सिलीगुड़ी जंक्शन, सीतारामपुर, सिउड़ी, सोनारपुर जंक्शन, सुईसा, तामलुक, तारकेश्वर, तुलिन, उलुबेरिया

पश्चिम बंगाल में स्थित वे स्टेशन जहां कार्य पूरे कर लिए गए हैं:

पश्चिम बंगाल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंगर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में उन स्टेशनों के नाम जहां कार्य पूरा हो गया है, का विवरण निम्नलिखित है:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पश्चिम	13	अनारा, बाराभूम, दीघा, गड़बेता, हल्दिया, हल्दीबाड़ी, जलपाईगुड़ी रोड,

बंगाल		जॉयचंडी पहाड़ जं, कल्याणी घोषपाड़ा, कामाख्यागुड़ी, पानागढ़, सिउड़ी, तमलुक

पश्चिम बंगाल के अन्य स्टेशनों पर भी विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं और कुछ स्टेशनों पर कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:

- आसनसोल जं. स्टेशन: दक्षिण विंग के नए स्टेशन भवन ब्लॉक संख्या 4, उत्तरी विंग के भवन ब्लॉक संख्या 1, 2 और 3 का संरचनात्मक पूरे कर लिए गए हैं। दक्षिण विंग के नए स्टेशन भवन ब्लॉक संख्या 3 का संरचनात्मक कार्य, 6 मीटर चौड़े ऊपरी सड़क पुल का विस्तार और एयर कॉनकोर्स का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन: द्वितीय प्रवेश द्वार पर नए स्टेशन भवन, रेल डाक सेवा कार्यालय भवन के निर्माण और चौथे तल तक नए प्रस्थान स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर नए आगमन स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य, नए प्रस्थान स्टेशन भवन के पांचवें और छठे तल के संरचनात्मक कार्य, पोडियम पार्किंग, एलिवेटेड रोड और एयर कॉनकोर्स के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- अलुआबाडी रोड स्टेशनः प्लेटफार्म संख्या 2 के विस्तार, प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 की सतह में सुधार, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, पहुंच मार्ग और चहारदीवारी के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पार पुल, नए स्टेशन भवन ब्लॉक और प्लेटफार्म शेल्टर में सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।
- न्यू फरक्का जंक्शन स्टेशन: स्टेशन भवन में सुधार, प्रतीक्षालयों, शौचालय, प्रवेश बरामदा, संकेतकों तथा रेलगाड़ी संकेतक बोर्ड की संस्थापना के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। परिचलन क्षेत्र के सुधार तथा पार्किंग के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- बर्द्धमान स्टेशन: द्वितीय प्रवेश द्वार पर नए स्टेशन भवन का निर्माण, प्रवेश द्वार बरामदा, प्रतीक्षालय, बुकिंग काउंटर, शौचालय, प्लेटफॉर्म सतह और प्लेटफॉर्म शेल्टर में

सुधार के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 6 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पार पुल और परिचलन क्षेत्र में सुधार के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों पर विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता सापेक्ष प्राथमिकता के अध्यधीन और धन की उपलब्धता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य स्टेशन की कोटि/स्थिति/सम्हाले जाने वाले यातायात आदि के आधार पर किए जाते हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल रेलवे स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि रेलवे स्टेशन-वार या राज्य-वार। पश्चिम बंगाल राज्य चार क्षेत्रीय रेलों अर्थात् पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,231 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 471 करोड़ रुपए (जून, 2026 तक) का व्यय उपगत किया गया है।

****